

# व्यूज टुडे

## वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेक्स/ WAVES), 2025 का उद्घाटन किया गया

वेक्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को भविष्य की GDP में वृद्धि, नवाचार और समावेशी विकास के एक शक्तिशाली चालक के रूप में रेखांकित किया।

- वेक्स का लक्ष्य 2029 तक 50 बिलियन डॉलर का बाजार तैयार करना है। इससे वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
- शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने रचनात्मक क्षेत्र के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT) स्थापित करने की घोषणा की।
  - इसकी स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा FICCI और CII के साथ रणनीतिक साझेदारी में की जाएगी। साथ ही, इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई है।

क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है?

- परिभाषा: क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है। यह आर्थिक संवृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान एवं क्षमता पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है।
  - इसमें मीडिया और मनोरंजन, विज्ञापन एवं मार्केटिंग, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) आदि शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने इसके वैश्विक महत्त्व पर जोर देते हुए वर्ष 2021 को "सतत विकास के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" घोषित किया था।

क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- क्रिएटिव इकोनॉमी फंड: सरकार ने 1 बिलियन डॉलर के क्रिएटिव इकोनॉमी फंड की घोषणा की है।
- ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी (AIICE): भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स (CCI) द्वारा भारत के रचनात्मक उद्योगों की विशाल क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।
- नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स: भारत में नवाचार और ऑनलाइन रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के कार्य को मान्यता देता है।

भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी

- योगदान: यह GDP में 30 बिलियन डॉलर का योगदान देती है एवं 8% कार्यबल को रोजगार प्रदान करती है। क्रिएटिव एक्सपोर्ट सालाना 11 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- चुनौतियां: गलत सूचनाओं का प्रसार, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता और बाजार पर एकाधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों की सीमित डिजिटल पहुंच और औपचारिक वित्त-पोषण की कमी आदि।

## सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फॉलोअर्स की कम होती संख्या के कारण आत्महत्या कर ली

लोकप्रिय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल ने अपने फॉलोअर्स की संख्या में गिरावट के कारण भावनात्मक रूप से संघर्ष करते हुए आत्महत्या कर ली।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से क्यों पीड़ित हैं?

- वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच बहुत बड़ा अंतर: एक प्रभावशाली व्यक्ति होना ग्लैमरस, उपहारों, स्पॉन्सर्ड ट्रिप एवं प्रसिद्धि से भरा हुआ लगता है।
  - हालांकि, इन्फ्लुएंसर के लिए हमेशा ऑनलाइन रहना एक पूर्णकालिक पेशा है। लगातार पोस्ट करने, जुड़ने और प्रदर्शन करने का दबाव गोपनीयता को खोने, थकान एवं चिंता का कारण बनता है।
- मान्यता और ऑनलाइन सूक्ष्म परीक्षण: इन्फ्लुएंसर्स को लाइक, कमेंट एवं फॉलोअर्स हासिल करने तथा अपने आत्मसम्मान को सोशल मीडिया की लोकप्रियता से जोड़ने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
  - हालांकि, ट्रेलिंग, दुर्व्यवहार या आलोचना के माध्यम से नकारात्मक फीडबैक गंभीर भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है।
- विषाक्त तुलना: सावधानीपूर्वक एडिटेड और क्यूरेटेड कंटेंट से घिरे रहने से जीवनशैली, रिश्तों को निभाने आदि के संबंध में हानिकारक सामाजिक तुलना हो सकती है।
  - अध्ययन इसे इन्फ्लुएंसर्स एवं उनके दर्शकों के बीच अवसाद और चिंता के उच्च स्तर से जोड़ते हैं।

## इन्फ्लुएंसर का मानसिक स्वास्थ्य क्यों मायने रखता है



### 13.6 बिलियन डॉलर का वैश्विक उद्योग आर्थिक योगदान

यूके हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट के अनुसार, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री अब वैश्विक स्तर पर 13.6 बिलियन डॉलर की है।



### इन्फ्लुएंसर, आधुनिक रोल मॉडल के रूप में

इन्फ्लुएंसर्स खासकर युवाओं के बीच रुझान, राय और व्यवहार को आकार देते हैं। वे अक्सर रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं।



### मानसिक स्वास्थ्य संकट की अनदेखी

बावजूद इसके कि इस पर शोध बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया युवा उपयोगकर्ताओं व इन्फ्लुएंसर्स के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है।

उनके करियर को लेकर हेय भावना: कई इन्फ्लुएंसर्स यह महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जाता है या उनकी आलोचना की जाती है, क्योंकि उनके पेशे को हमेशा गंभीरता से नहीं लिया जाता।

जैसे-जैसे अधिकाधिक जीवन ऑनलाइन होता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को समझना तथा उनका समर्थन करना अत्यंत आवश्यक होता जा रहा है।

## नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है

केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को कृषि, निवेश और निर्यात जैसे क्षेत्रों के साथ जोड़ते हुए उन्हें देश की विकास यात्रा के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में महत्व दिया गया है। MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में क्या चुनौतियां हैं?

- औपचारिककरण: अनौपचारिक क्षेत्र में MSMEs की हिस्सेदारी लगभग 90% है (ILO, 2023)।
- वित्त की कमी: सीमित औपचारिक ऋण और उच्च जोखिम की संभावना के कारण MSMEs को 80 लाख करोड़ रुपये के ऋण की कमी का सामना करना पड़ रहा है (क्रिसिल के अनुसार)।
- कौशल की कमी: वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (WIPO, 2023) के अनुसार, ज्ञान-आधारित रोजगार में 3.9% की गिरावट (लगभग 13% से) MSMEs की नवाचार और विकास क्षमता को प्रभावित कर रही है।
- आंकड़ों का अभाव: MSMEs से जुड़ी नौकरियों, निर्यात और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विश्वसनीय एवं विस्तृत आंकड़ों की अनुपलब्धता, प्रभावी नीति निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बनती है।
  - यहां तक कि उद्यम (UDYAM) डेटाबेस में भी विस्तृत जानकारी का अभाव है। इससे नीतिगत निर्णयों में बाधा आती है।
- अन्य मुद्दे: MSMEs को कम उत्पाद विविधता, पुरानी तकनीक और "मिसिंग मिडल (विनिर्माण में बहुत कम मध्यम आकार की फर्म)" से जूझना पड़ रहा है।

### MSMEs: भारत की आर्थिक संवृद्धि का अहम स्तंभ

भारत के GVA में हिस्सेदारी  
**27.3% → 30.1%**  
(2020-21 से 2022-23 तक)



क्षेत्रक-वार योगदान  
**36%**  
विनिर्माण द्वारा  
**45.7%**  
निर्यात द्वारा

MSME निर्यात वृद्धि  
**3.95 लाख करोड़ रुपये**  
(2020-21)  
↓  
**12.39 लाख करोड़ रुपये**  
(2024-25)

MSMEs की श्रेणी	निवेश (करोड़ रुपये में)	टर्नओवर (करोड़ रुपये में)
सूक्ष्म	≤ 2.5	≤ 10
लघु	≤ 25	≤ 100
मध्यम	≤ 125	≤ 500

MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु उपाय

- वित्ती की सुलभता: क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMS) में सुधार, NBFCs को समर्थन प्रदान करना, तथा राज्य स्तरीय सब्सिडी मानदंडों को आसान बनाना।
- कौशल प्रशिक्षण: औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों, MSMEs के मालिकों के लिए वित्तीय साक्षरता, और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- डेटा: बेहतर नीति निर्धारण के लिए उद्यम पोर्टल को विस्तृत, क्लस्टर-वार और राज्य-स्तरीय डेटा के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार: लघु फर्मों के लिए लक्षित नीतियां बनाना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कोलेबोरेशन (IFC) को मजबूत करना चाहिए।

## ओडिशा सरकार ने शहरी गरीबों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए 'सहयोग (Sahajog) पहल' शुरू की

ओडिशा सरकार की 'सहयोग' पहल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- शहरी गरीब समुदायों में पाल लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें जन जागरूकता के माध्यम से उपयुक्त योजनाओं से जोड़ना,
- पाल लाभार्थियों के घर तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना, आदि।

भारत में शहरी गरीबी

- ग्रामीण गरीबी की तरह ही शहरी गरीबी भी रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं और शिक्षा प्राप्ति में समस्याओं से जुड़ी हुई है। साथ ही, जिन समुदायों के बीच शहरी गरीब निवास करते हैं वहां भी उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।
- हाल में जारी विश्व बैंक की "पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ" रिपोर्ट के अनुसार, शहरी भारत में चरम गरीबी की दर 17.2% है, जबकि ग्रामीण भारत में यह मात्र 2.8% है।

शहरी गरीबी में जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों है?

- अधिक दैनिकीय जीवन-यापन: शहरी गरीब बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और वेंटिलेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है।
  - शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, शिक्षा, परिवहन और आवास महंगे होते हैं। ज्यादातर लोग इन सेवाओं को वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में समस्या: पहचान पत्र या आवास प्रमाण पत्र नहीं होने से शहरों में रहने वाले प्रवासी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी आय समर्थन योजना भी नहीं चलाई जा रही है।
- असमानता: ग्रामीण गरीबी की तुलना में शहरी गरीबी तुरंत दिख जाती है क्योंकि शहरी गरीबों की आबादी घनी और झुग्गी बस्तियों में केंद्रित होती है। इससे गरीबों को अपनी गरीबी और सामाजिक उपेक्षा का अधिक एहसास होता है।
  - उदाहरण: मुंबई की धारावी मलिन बस्ती के पास बनी लज्जरी और ऊंची इमारतें इस गहरी असमानता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
- सामाजिक सहायता में कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामुदायिक जीवन जीते हैं। इसके विपरीत, शहरों में मजबूत सामुदायिक संबंध और पारंपरिक सामाजिक नेटवर्क नहीं होते। इससे अकेलेपन और मानसिक बीमारियों का खतरा बना रहता है।
- उपेक्षित नगरीकरण: प्रायः शहरी योजना-निर्माण में झुग्गियों जैसी अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाली आबादी की उपेक्षा कर दी जाती है।

### शहरी गरीबी को कम करने के लिए उठाए गए कदम



**आवास:** प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य



**सैनिटेशन:** कार्याकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 (AMRUT-2.0)



**रोजगार सृजन और कौशल विकास:** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM); पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि)।



**खाद्य सुरक्षा:** 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के तहत एक ही राशन कार्ड से देशभर में किसी भी जगह पात्र लाभार्थियों को राशन की सुविधा।



**स्वास्थ्य:** आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत भारत के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा; प्रधान-मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत लाभ प्राप्ति के लिए स्व-प्रमाणन की सुविधा।

## कैंसर के इलाज में नवीन CAR-T थेरेपी के आशाजनक परिणाम सामने आए

ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक नई थेरेपी, HSP-CAR30 विकसित की है, जो CD30 नामक प्रोटीन को लक्षित करती है। यह थेरेपी अपने शुरुआती परीक्षणों में सफल रही है।

➤ CD30 प्रोटीन कुछ T कोशिकाओं और B कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह कैंसर के निदान और उपचार में मदद करता है।

- ⊕ ध्यान रखें कि T और B दोनों कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं।
- ⊕ T कोशिकाएं साइटोटॉक्सिक प्रकृति की होती हैं। उनका मुख्य कार्य शरीर में हानिकारक या संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना होता है।

### प्रमुख विकास-क्रम

➤ बेहतर प्रभावशीलता: इस थेरेपी ने 100% मरीजों में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, और 50% मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए।

➤ सुरक्षा और प्रतिरक्षा: इस उपचार में कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। इसके अलावा, इलाज के एक साल बाद तक CAR30+ कोशिकाएं 60% मरीजों के शरीर में मौजूद रहीं।

### कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल (CAR-T) थेरेपी क्या है?

➤ कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल (CAR-T) थेरेपी एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर के इलाज में उपयोग होती है। इसमें मरीज के T कोशिकाओं को रक्त से एकत्र किया जाता है और प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है।

➤ इन T कोशिकाओं में एक विशेष रिसेप्टर डाला जाता है जिसे CAR (कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर) कहा जाता है। यह रिसेप्टर T कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम बनाता है।

➤ CAR-T थेरेपी ने पहले से ही कुछ रक्त कैंसर जैसे एक्वट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL), नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा के इलाज में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है।

CAR-T थेरेपी के लाभ	चुनौतियां
➔ <b>लंबे समय तक राहत:</b> CAR-T थेरेपी कैंसर को लंबे समय तक दूर रख सकती है, जिससे बार-बार इलाज की जरूरत कम होती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है।	➔ <b>साइटोकाइन रिजिलेन्स सिंड्रोम (CRS):</b> यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, जो CAR-T कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए साइटोकाइन्स के कारण होती है। इससे कई अंगों की कार्यक्षमता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर ठीक हो जाती है।
➔ <b>व्यक्तिगत इलाज:</b> इस थेरेपी में मरीज की T कोशिकाओं को ही संशोधित करके उपयोग किया जाता है, जिससे इलाज अधिक प्रभावी होता है और दुष्प्रभाव कम होते हैं।	➔ <b>न्यूरो-टॉक्सिसिटी (मस्तिष्क में जड़ जटिलताएं):</b> इसमें सिरदर्द, भ्रम, दौरे (सीज़म), मस्तिष्क में सूजन (सेरेब्रल एडीमा) और कोमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
➔ <b>कम समय में इलाज:</b> उपचार लगभग 45 दिनों में पूरा हो जाता है।	➔ <b>एंटीजन पहचान:</b> कुछ ट्यूमर खूब को बचाने के लिए उस एंटीजन को छीं देते हैं जिसे CAR-T कोशिकाएं पहचानती हैं। इसके कारण इलाज का असर कम हो जाता है।

## गुंडारम शिलालेखों से सातवाहन काल के नए तथ्य सामने आए हैं

गुंडारम रिजर्व फॉरिस्ट में मिले 11 शिलालेख प्राचीन दक्कन की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शिलालेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक के हैं, और विशेष रूप से सातवाहन काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए अहम माने जाते हैं।

### शिलालेखों से प्राप्त मुख्य जानकारी

➤ हरितिपुत्र शिलालेख: प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया यह शिलालेख सातवाहन और चुटु राजवंशों के बीच राजनीतिक गठबंधन का संकेत देता है।

⊕ चुटु राजवंश (Chutu Dynasty) सातवाहनों का समकालीन था।

➤ त्रिशूल और डमरू शिलालेख: त्रिशूल और डमरू के चिन्ह वाला यह अनोखा शिलालेख दक्षिण भारत में अब तक ज्ञात सबसे प्रारंभिक धार्मिक प्रतीकों में से एक को दर्शाता है।

⊕ यह शिलालेख राजनीतिक सत्ता और धार्मिक प्रतीकों के बीच प्रारंभिक संबंध को दर्शाता है।

### सातवाहन वंश (दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी):

➤ पुराणों में सातवाहन वंश को 'आंध्रभृत्य या आंध्र' भी कहा गया है। यह मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र (आधुनिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र) में स्थापित एक प्रमुख राजवंश था।

### प्रमुख शासक:

⊕ सिमुक: उसने कण्व वंश को हटाकर सातवाहन वंश की स्थापना की।

⊕ गौतमीपुत्र शातकर्ण: उसके शासन काल में सातवाहन साम्राज्य अपनी चरम पर पहुंच गया। वह शकों (पश्चिमी क्षत्रप) के विरुद्ध सैन्य सफलताओं और सातवाहन साम्राज्य के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है।

◆ नासिक और नानाघाट शिलालेख उसके शासन-काल के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।

⊕ हाल सातवाहन: वह अपनी प्रसिद्ध 'प्राकृत' काव्य रचना 'गाथासप्तशती' के लिए प्रसिद्ध है।

➤ सातवाहन शासकों की एक खास विशेषता यह थी कि उन्होंने कई बार अपनी माता के नाम को अपने शाही नाम का हिस्सा बनाया, जो उस समय के अन्य राजवंशों से अलग परंपरा थी।

➤ सातवाहन उन प्रथम भारतीय राजवंशों में शामिल थे जिन्होंने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए।

## अन्य सुर्खियां

### नमस्ते (NAMASTE) योजना अंतर्गत UNDP-भारत सहयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा UNDP नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना के तहत इसके कचरा बीनने वालों के घटक के तहत सहयोग कर रहे हैं।

➤ UNDP इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (PMUs) को वित्तीय सहायता दे रहा है।

➤ स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए 2023 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते योजना शुरू की गई थी।

### नमस्ते योजना के कचरा बीनने वालों के घटक के बारे में

➤ प्रारंभ: इसे 2024 में शुरू किया गया था।

➤ उद्देश्य:

⊕ पूरे भारत में कचरा बीनने वाले 2.5 लाख लोगों का डिजिटल प्रोफाइल तैयार करना और उनका पंजीकरण करना।

⊕ आयुष्मान भारत-PMJAY के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, आदि की व्यवस्था करना।

➤ सामूहिकीकरण: कचरा बीनने वालों के संगठन को बढ़ावा देना, उन्हें विकेन्द्रित कचरा संग्रहण केन्द्रों (DECCs) का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना तथा उनकी आजीविका में सुधार करना।

### आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क (Victims of Terrorism Associations Network: VoTAN)

संयुक्त राष्ट्र-आतंकवाद-रोधी कार्यालय (UNOCT) ने आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क (VoTAN) शुरू किया है। यह आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सहायता देने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है।

### VoTAN के बारे में

➤ पृष्ठभूमि: स्पेन और इराक की अध्यक्षता में "द युप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिमस ऑफ टेररिज्म" की स्थापना लगभग छह साल पहले आतंकवाद पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी।

➤ स्थापना: यह नेटवर्क "आतंकवाद के पीड़ितों पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस 2022" का एक प्रमुख आउटकम है।

➤ लक्ष्य:

⊕ आतंकवाद से पीड़ितों और बचे लोगों को एक-दूसरे का समर्थन करना,

⊕ उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना;

⊕ उन्हें अधिकारों, शिक्षकों और शांति-स्थापकों के रूप में संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान करना।

➤ वित्तीय सहायता: स्पेन से प्राप्त होती है।



### राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) में एक नए अध्यक्ष के साथ-साथ 7 नए सदस्यों की नियुक्ति की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के बारे में

- इसका गठन पहली बार दिसंबर 1998 में केंद्र सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सलाहकार संस्था के रूप में किया गया था। इस बोर्ड में उद्योग और मीडिया जगत, सिविल सोसाइटी इत्यादि के सदस्य शामिल होते हैं।
- इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- कार्य: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दीर्घकालिक विश्लेषण प्रदान करना तथा इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) को अपना विचार प्रदान करना।
- यह बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए किसी विषय पर उपायों और नीतिगत विकल्पों की भी सिफारिश करता है।



### गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2025

केंद्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की जगह गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2025 जारी किया है। इसका उद्देश्य गन्ना क्षेत्रक के विनियमन में सुधार करना है।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2025 के मुख्य बिंदु

- रियल टाइम आधार पर डेटा उपलब्ध कराना: चीनी मिलों और खाद्य विभाग के पोर्टल के बीच एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का एकीकरण किया जाएगा, ताकि रियल टाइम में डेटा प्राप्त हो सके।
- अधिक उत्पादों को शामिल किया गया: नए आदेश के तहत खांडसारी (कच्चे गन्ने के रस से बनी अपरिष्कृत चीनी) और कच्ची चीनी को शामिल किया गया है, ताकि इन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके और किसानों को उचित मूल्य दिलाया जा सके।
- नए बाय-प्रोडक्ट शामिल: देश में चीनी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुड़ और इथेनॉल को विनियमन के दायरे में लाया गया है।
- मानक परिभाषा: संपूर्ण चीनी उद्योग में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु चीनी उत्पादों के लिए FSSAI की परिभाषाओं को अपनाया गया है।



### मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

सालिकसाईंरंजी और चिराग शेठ्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह बैडमिंटन जोड़ी 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर पहुंच गई थी। उन्होंने हांग्जो में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में

- उत्पत्ति: यह पुरस्कार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्थापित हुआ था, और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया।
- इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है।
- उद्देश्य: यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।
- पालता: इस पुरस्कार के लिए केवल मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किए गए प्रदर्शन पर ही ध्यान दिया जाता है।
- पुरस्कार: 25 लाख रुपये नकद पुरस्कार, पदक और सम्मान प्रमाण पत्र।
- पुरस्कारों की संख्या: सामान्यतः प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है।



### इंडो-पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवरनेस (IPMDA)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो-पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवरनेस (IPMDA) को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत को एक सैन्य उपकरण और लॉजिस्टिक समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है।

IPMDA के बारे में

- IPMDA एक तकनीकी और प्रशिक्षण पहल है। इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री निगरानी को बढ़ाना और इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जलमार्गों की आवाजाही में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इस पहल की घोषणा क्वाड (QUAD) के सदस्य देशों ने 2022 में टोक्यो शिखर सम्मेलन में की थी।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं।
- यह पहल इनोवेटिव तकनीक का उपयोग करती है ताकि दक्षिण-पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र के साझेदार देशों को उनके समुद्री क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों की लगभग रियल टाइम की जानकारी मिल सके।



### ऑपरेशन हॉक (Operation Hawk)

CBI ने 'ऑपरेशन हॉक' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना है।

यह कार्रवाई ऑपरेशन कार्बन (2021) और ऑपरेशन मेघ चक्र (2022) की अगली कड़ी है। इनका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जुड़े संदिग्धों की पहचान करना और उनके नेटवर्क को समाप्त करना है।



### लक्कुंडी मंदिर

लक्कुंडी मंदिरों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने की संभावना है।

लक्कुंडी मंदिर के बारे में

- यह कर्नाटक के गडग जिले में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में लक्कुंडी को 'लोक़ी गुंडी' कहा गया है।
- ये मंदिर कल्याण चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे।
- पुरे गांव में 50 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं और 101 सीढ़ीनुमा कुएं हैं जिन्हें कल्याणी भी कहा जाता है।
- इनमें से कसी विश्वनाथ मंदिर सबसे अधिक अलंकृत और विस्तृत रूप से सुसज्जित मंदिर है।
- यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है।
- इसमें महावीर को समर्पित एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है, जो लक्कुंडी में सबसे बड़े और सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है।



### यू.एस.ए.-यूक्रेन खनिज और ऊर्जा समझौता

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत यूक्रेन के खनिज और ऊर्जा भंडार (नई तेल और गैस परियोजनाओं सहित) के उपयोग में अमेरिका को वरीयता दी जाएगी।

यूक्रेन के खनिज भंडार के बारे में

- रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs): यह 17 भू-धातुओं का एक समूह है। ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है।
- क्रिटिकल मिनरल्स: ये दुर्लभ खनिज होते हैं। अलग-अलग देशों की क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में अलग-अलग मिनरल्स शामिल हैं।
- अमेरिका ने जिन 50 स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल किया है, उनमें से 22 मिनरल्स यूक्रेन में प्राप्त होते हैं। इनमें ग्रेफाइट और लिथियम शामिल हैं।
- भारत ने 30 खनिजों को "क्रिटिकल मिनरल्स" की सूची में शामिल किया है।

## सुर्खियों में रहे स्थल



### मिस्र (राजधानी: काहिरा)

भारत और मिस्र ने संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक में आतंकवाद विरोधी सहयोग को नई दिशा दी।

राजनीतिक विशेषताएं

- अवस्थिति: मिस्र अफ्रीका के सुदूर उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है।
- सीमावर्ती देश: लीबिया (पश्चिम में), सूडान (दक्षिण में), और इजरायल (उत्तर-पूर्व में)।
- सीमावर्ती जल निकाय: भूमध्य सागर (उत्तर में), लाल सागर और अकाबा की खाड़ी (पूर्व में)।

भौगोलिक विशेषताएं

- प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: रेड सी हिल्स, सिनाई पर्वत, आदि।
- उच्चतम शिखर: माउंट कैथरीन (2,642 मीटर)
- प्रमुख नदी: नील नदी
- प्रमुख रेगिस्तान: पश्चिमी रेगिस्तान (Al-Şaḥrā' al-Gharbiyyah), पूर्वी रेगिस्तान (Al-Şaḥrā' al-Sharqiyyah)।

